Default in Wages and Salaries in P.S.Us.

1470. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aw are that there has been delay or de fault in payment of wages and sala-vies in a number of public sector undertakings in the country; and

(b.) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes Sir.

(b) As and when such instances are brought to the notice of the Go. vetnment urgent remedial measures are suggested to the PSE by the administrative Ministry concerned.

Utilisation of Rupee Repayment Fund for industrial projects

1471. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that India and Russia have recently agreed to utilise aportion of the Rupee Repayment Fund to finance construction and modernisation of industrial projects in India and also to make conetribution to the equity of Indo-Russian joint ventures operating in India; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) (a) and (b) During the Prime Minister's visit to Moscow from 29th June to 2nd July, 1994, the questions relating to repayment of outstanding debt by India to Russia were discussed. It was agreed that the rupee balances due to Russia on account of debt repayment could be used to invest in agreed projects in India. The rupee funds can also be used to import machinery and equipment for modernisation of projects in Russia. However, no concrete proposals have yet been received, and the detailed modalities are yet to be agreed upon between the two sides.

कच्छ में उद्योगों की स्थापना के लिए समिति

1472. श्रीमती चन्द्रिका अमिन दन जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्छ के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापति करने और जन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र, के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्रान्ति लाने और इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : ('क) जी, नहीं।

(ख) यह राज्य सरकारों का उत्तर-दायित्व है कि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जा सकें। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये पूरे देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्राधनमंत्री की रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कच्छ के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और रोजगार पैदा करने के लिए कई योजनायें भी कार्यान्वित कर रहा है।